RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 21 से 27 मार्च 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-84 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

मुद्रा योजना के तहत अब तक 39.48 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत, एनपीए मात्र 2% के आसपास: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

छोटे उद्यमियों को मजबूत सहारा, 50 करोड़ से अधिक लोन दिए गए; कम एनपीए दर से योजना की सफलता साबित, वित्तीय समावेशन में नया कीर्तिमान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM-MUDRA) शुरू होने के बाद से अब तक कुल ₹39.48 लाख करोड़ रुपये के लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा योजना की भारी सफलता को दर्शाता है। योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों और माइक्रो उद्योगों को लोन दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा लोन का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) रेशियो मात्र 2% के आसपास है, जो बैंकिंग क्षेत्र के औसत से काफी बेहतर है। उन्होंने इसे योजना की मजबूत क्रेडिट डिसिप्लिन और प्रभावी मॉनिटरिंग का नतीजा बताया। सीतारमण ने बताया कि शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में दिए गए लोन ने लाखों युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

PM-MUDRA योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बिना गारंटी के छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अधिकतम ₹10 लाख तक का लोन बिना कोलेटरल के दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कम NPA दर और विशाल स्वीकृत राशि मुद्रा योजना को देश की सबसे सफल वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक बनाती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि आगे डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट और स्किल ट्रेनिंग को और मजबूत किया जाए।

सरकार का लक्ष्य है कि मुद्रा योजना के तहत आने वाले वर्षों में और अधिक छोटे उद्यमियों तक पहुंच बनाई जाए। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

सरकार को FY26 में अतिरिक्त ₹2.01 लाख करोड़ खर्च करने की संसद से मंजूरी

पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा, कुल बजट व्यय अब ₹50.65 लाख करोड़ पहुंचा; विकास और रोजगार पर मजबूत फोकस

नई दिल्ली: केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अतिरिक्त ₹2.01 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। संसद ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के जरिए इस प्रस्ताव को पास कर दिया। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष का कुल बजट व्यय ₹50.65 लाख करोड़ हो गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर), रेलवे, सड़क निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज गति देने, MNREGA जैसे रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत करने और किसानों के लिए फसल बीमा तथा सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह अतिरिक्त फंड मांगा था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा, “यह अतिरिक्त व्यय विकास की गति को बनाए रखने और आम जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी था। हम इंफ्रा पर खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहे हैं।”

विपक्ष ने कुछ मदों पर सवाल उठाए, लेकिन कुल मिलाकर प्रस्ताव व्यापक समर्थन से पास हो गया। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह अतिरिक्त खर्च GDP ग्रोथ को 0.3-0.4 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त समर्थन दे सकता है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को फायदा होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को रूस, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ाना चाहिए। साथ ही, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना होगा। RBI को भी ब्याज दरों सरकार का कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर अब ₹11.21 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। यह कदम 8%+ GDP ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अतिरिक्त व्यय चुनावी वर्ष से पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की साफ रणनीति है। आने वाले महीनों में इन फंड्स के प्रभावी उपयोग पर नजर रहेगी।

टाटा स्टील अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NINL का विलय करेगी, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने का लक्ष्यछूट

2.2 मिलियन टन क्षमता वाले प्लांट का विलय, लागत बचत और दक्षता बढ़ाने का कदम;

स्टील प्रोडक्शन में मजबूती, 2030 तक 40 MTPA क्षमता का लक्ष्य

नई दिल्ली: टाटा स्टील लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नीरो अयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (NINL) का विलय करने का फैसला लिया है। यह कदम कंपनी के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने, लागत कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से उठाया गया है। NINL की 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली स्टील प्लांट को टाटा स्टील के मुख्य ऑपरेशंस में शामिल किया जाएगा।

टाटा स्टील के एमडी टी.वी. नरेंद्रन ने कहा, यह विलय हमारी रणनीति का हिस्सा है। NINL का विलय करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी, डुप्लिकेट खर्च कम होंगे और हम ज्यादा वैल्यू-एडेड स्टील प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकेंगे। NINL ओडिशा के केंदुझर में स्थित है और मुख्य रूप से पिग आयरन और बिलेट का उत्पादन करती है। विलय के बाद इस प्लांट को टाटा स्टील के व्यापक नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी।

यह फैसला टाटा स्टील के 2030 तक 40 MTPA स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य से जुड़ा है। कंपनी पहले से ही कालिंगानगर और मेरामंडली में बड़े विस्तार कर रही है। NINL का विलय लागत दक्षता बढ़ाने और मार्जिन सुधारने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टाटा स्टील को बाजार में और मजबूत बनाएगा। विलय प्रक्रिया NCLT की मंजूरी के बाद पूरी होगी। टाटा स्टील के शेयर बाजार में चढ़े। यह विलय स्टील सेक्टर में एकीकरण और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का बेहतरीन उदाहरण है।

Axis Bank to Invest Rs 1,500 Crore in Consumer Lending Arm Amid Stake Sale Rethink

Move Signals Shift from Potential Divestment to Aggressive Growth Strategy; Retail Loan Book Targeted to Cross ₹3 Lakh Crore by FY28

Mumbai: Axis Bank has decided to inject ₹1,500 crore of fresh capital into its wholly-owned consumer lending subsidiary, Axis Finance Ltd, even as it reconsiders plans to sell a minority stake in the arm. The move underscores the bank's renewed confidence in the retail lending business and its intention to accelerate growth in the high-margin consumer segment.

The capital infusion will be used to expand Axis Finance's loan book, strengthen its digital lending platform, and deepen penetration in personal loans, credit cards, two-wheeler financing, and small-ticket business loans. The subsidiary currently has an asset under management (AUM) of around ₹48,000 crore and has been growing at over 25% annually.

Consumer lending remains a strategic priority for the group. We see significant headroom for profitable growth and have therefore decided to further strengthen the balance sheet of Axis Finance, said a senior Axis Bank executive. The bank had earlier explored selling up to 20-25% stake in the subsidiary to strategic or financial investors, but those discussions have been put on hold for now.

The decision comes at a time when Axis Bank is aggressively expanding its retail franchise to reduce dependence on corporate lending. The bank aims to grow its overall retail loan book to over ₹3 lakh crore by FY28. The fresh capital will also help Axis Finance improve its credit rating and lower its cost of funds.

Analysts welcomed the development, noting that consumer lending yields are significantly higher than corporate lending. However, they cautioned that rising competition and potential asset quality pressures in the unsecured segment would require strong underwriting discipline.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

War and Oil: Lessons from Past Conflicts and What the Iran–Israel Crisis Means Today

Whenever a war breaks out anywhere in the world, one of the first things that gets affected is oil prices. Oil is the backbone of the global economy it powers transport, industries, and daily life. History shows that almost every major war has led to a sharp rise in oil prices, and the ongoing Iran–Israel conflict is following the same pattern.

Let us first understand the past. During the Gulf War in 1990, oil prices doubled in a short time because supply from the Middle East was disrupted. Similarly, during the Russia–Ukraine war in 2022, oil prices surged to nearly $130 per barrel, leading to global inflation. Transport costs increased, food prices went up, and many countries faced economic slowdown. These events clearly show that war in key energy regions directly impacts the global economy.

Now, in 2026, the Iran–Israel conflict is again creating similar concerns. The biggest worry is disruption in the Strait of Hormuz, a narrow sea route through which nearly 20% of the world's oil supply passes. Even the fear of disruption is enough to push oil prices higher.

Recent reports show how serious the situation has become. Oil prices have surged sharply, and in some cases, crude prices for Indian buyers have jumped close to $130–$150 per barrel levels due to supply fears. This sudden increase reflects how sensitive oil markets are to geopolitical tensions.

So, why does this matter so much for India?

India is the third-largest oil consumer in the world and imports around 85–90% of its crude oil needs. This means when global oil prices rise, India must spend more money on imports. As a result: Petrol and diesel prices increase, Transportation becomes expensive, Cost of goods and services rises and Inflation goes up

Even a small increase in oil prices can have a big impact. Experts say that a $10 rise in crude oil can significantly increase India's import bill and widen the fiscal gap. The effect does not stop at fuel. Higher oil prices increase the cost of fertilizers, electricity, manufacturing, and logistics. This eventually leads to higher prices of food and daily-use items. In simple terms, when oil becomes expensive, everything becomes expensive.

Global markets also react strongly during such times. Investors become cautious and shift money from stocks to safer assets like gold. Stock markets often fall or become highly volatile because companies face higher costs and lower profits.

However, there is also an important lesson from past wars. While oil prices rise sharply in the short term, they usually stabilise once the situation improves. For example, after the initial shock of the Russia–Ukraine war, oil prices gradually cooled down as supply adjusted.

The current Iran–Israel conflict is still evolving, and its long-term impact will depend on how long it continues and whether supply routes remain open. If the conflict escalates further, oil prices could remain high for a longer period, increasing pressure on global and Indian economies.

In conclusion, history clearly shows that war and oil are closely connected. Every major conflict leads to energy price shocks, which then affect inflation, growth, and markets. For India, being heavily dependent on oil imports makes it more vulnerable to such global events.

For common people, the message is simple: even if a war is happening far away, its impact can be felt in daily expenses. That is why global peace and stable energy supply are not just political issues, they are directly linked to our everyday economic life.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

ऑटो पार्ट्स उद्योग में LPG संकट से कर्मचारियों का पलायन, उत्पादन प्रभावित

गैस की कमी से छोटे-मध्यम यूनिट्स में काम बाधित, मजदूर गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत की ओर रुख कर रहे; उद्योग जगत में चिंता, सरकार से तत्काल राहत की मांग

मुंबई: देश के ऑटो कंपोनेंट उद्योग में घरेलू एलपीजी (LPG) की भारी कमी के कारण बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का पलायन शुरू हो गया है। विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा के छोटे-मध्यम उद्योगों (MSME) में काम करने वाले मजदूर अब बेहतर सुविधाओं और नियमित गैस सप्लाई वाले राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं।

उद्योग संगठनों ACMA और AIAM के अनुसार, पिछले दो महीनों में कई यूनिट्स में 15-25% कर्मचारी कम हो गए हैं। LPG की कमी से भट्टियां और फर्नेस नहीं चल पा रही हैं, जिससे उत्पादन 30-40% तक घट गया है। कई फैक्टरियां आंशिक रूप से बंद हैं या सिर्फ एक शिफ्ट चला रही हैं। इससे मजदूरों की आय प्रभावित हुई है और वे वैकल्पिक रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं।

ACMA के अध्यक्ष ने कहा, LPG संकट केवल उत्पादन की समस्या नहीं है, बल्कि यह स्किल्ड वर्कफोर्स को भी खोने की समस्या बन गया है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले महीनों में ऑटो कंपोनेंट सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो सकती है।

उद्योग का अनुमान है कि वर्तमान में 8-10 लाख टन LPG की कमी है। ऑटो पार्ट्स उद्योग में ज्यादातर छोटी यूनिट्स LPG पर निर्भर हैं क्योंकि यह सस्ता और आसानी से इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। सरकार से अब उद्योग जगत मांग कर रहा है कि ऑटो कंपोनेंट यूनिट्स को प्राथमिकता पर LPG सप्लाई दी जाए या उन्हें प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पलायन जारी रहा तो मार्च 2026 तक कई छोटी यूनिट्स बंद हो सकती हैं, जिसका असर पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग पर पड़ेगा। सरकार इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेने की तैयारी कर रही है।

India's AC Industry Braces for Supply Disruptions as LPG and Petrochemical Shortages Hit Amid West Asia Conflict

Rising Geopolitical Tensions Cause Sharp Spike in Input Costs; Manufacturers Warn of 8-12% Price Hikes and Possible Production Cuts This Summer

Bhopal: India's air conditioner industry is facing serious supply chain disruptions due to shortages of LPG and key petrochemicals triggered by the escalating conflict in West Asia. With Brent crude crossing $92 per barrel and LPG supplies tightening, manufacturers are grappling with a sudden surge in production costs.

According to industry body ISHRAE and major AC makers including Voltas, Daikin, LG, Blue Star, and Carrier, the cost of critical raw materials such as copper tubes, aluminium fins, compressors, and polyurethane foam used in insulation has risen sharply over the past three weeks. LPG, which is extensively used in manufacturing processes and as a feedstock for several petrochemical derivatives, has become particularly scarce and expensive.

Senior executives have warned that if the situation persists, AC prices could increase by 8-12% ahead of the peak summer season. Some companies have already begun revising prices for select models, while others are considering reducing production volumes to manage inventory and costs.

West Asia tensions have created a double impact, higher crude prices and direct disruption in LPG and chemical supplies. This is the worst input cost shock the industry has faced in the last three years, said a top official from a leading AC manufacturer.

The Indian AC market, which is expected to cross 10 million units this year, is highly sensitive to price changes. Any significant hike could dampen demand, especially in Tier-2 and Tier-3 cities where affordability plays a major role.

The government is closely monitoring the situation. Industry leaders have urged the Centre to ensure priority allocation of domestic LPG to manufacturing units and expedite alternative import channels.

With the conflict showing no immediate signs of resolution, India's $8 billion AC industry is preparing for a challenging summer season marked by higher prices and possible supply constraints.

Plastic Price Surge Hits MSMEs Hard, Disrupts Supply Chains for FMCG and Footwear Sectors

Petrochemical costs jump 18-25% in two months due to West Asia tensions; Small manufacturers face margin erosion, delayed orders, and risk of production cuts

Mumbai: A sharp rise in plastic and petrochemical prices is severely impacting India's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), creating widespread disruption in supply chains for fast-moving consumer goods (FMCG), footwear, packaging, and consumer durables industries.

According to industry associations, prices of key raw materials such as HDPE, LDPE, PP (polypropylene), and PVC have increased by 18-25% since November 2025, primarily due to escalating crude oil prices and supply constraints triggered by the West Asia conflict. Many MSME units, which form the backbone of plastic processing in the country, are struggling to absorb these costs as they operate on thin margins.

FMCG companies are facing delays in delivery of plastic bottles, caps, pouches, and laminated packaging, while footwear manufacturers are witnessing shortages of EVA soles, PVC straps, and synthetic leather. Several mid-sized footwear exporters in Agra, Chennai, and Kolkata have reportedly put fresh orders on hold.

Plastic is the single largest cost component for us. A 20%+ price increase cannot be fully passed on to buyers in the current weak demand environment," said the president of the All-India Plastics Manufacturers' Association (AIPMA).

Many MSMEs have resorted to reducing production shifts, delaying salaries, and in some cases, laying off temporary workers. The situation is particularly grim for units in Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu, which account for over 60% of India's plastic processing capacity.

Industry leaders have urged the government to intervene by reducing import duties on key petrochemicals, ensuring uninterrupted domestic supply of naphtha and LPG to crackers, and providing temporary relief under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme.

With the peak summer and festive season approaching, any further escalation in plastic prices could severely affect product availability and inflation in daily-use goods.

Hindalco Expects Sharp Rise in Aluminium Exports as War Disrupts Global Supply Chains

Red Sea crisis and West Asia conflict create supply shortage; Indian producer eyes 25-30% jump in overseas shipments in FY26

Pune: Hindalco Industries, India's largest aluminium producer, expects a significant increase in its export volumes this financial year as the ongoing conflict in West Asia and Red Sea disruptions severely affect global aluminium supply chains.

According to company executives, supply shortages from traditional producers in the Middle East and Europe, combined with higher shipping costs and delays, have created a favourable opportunity for Indian aluminium exports. Hindalco is targeting a 25-30% rise in aluminium exports during FY26 compared to the previous year.

Global customers are actively looking for reliable and alternative sources of aluminium. With our integrated operations, cost competitiveness, and strong focus on value-added products, we are well-positioned to capture this demand, said Satish Pai, Managing Director, Hindalco Industries.

The company's aluminium business has already seen strong export enquiries from Europe, South Korea, Japan, and Southeast Asia. Primary aluminium, aluminium billets, and value-added products such as rolled sheets and extrusions are witnessing particularly high demand.

Hindalco's aluminium smelters are currently operating at near-full capacity. The company is also accelerating production at its new facilities and expanding value-added downstream capacity to meet both domestic and international orders.

Analysts believe the current geopolitical situation could extend the tight supply scenario for several quarters, benefiting low-cost producers like Hindalco. However, they cautioned that any further escalation in crude oil prices or freight rates could partially offset the gains.

The development comes at a time when India is pushing for greater self-reliance and export growth in critical metals. Hindalco's strong performance is also expected to support the Aditya Birla Group's overall profitability in the current fiscal.

Ambani's $300 Billion Texas Bet: A Strategic Nod to MAGA and American Energy Dominance

Reliance's massive refinery project in Trump's home state signals deepening India-US economic ties and alignment with 'America First' energy policy

Ludhiana: In a landmark move that blends business strategy with geopolitical foresight, Mukesh Ambani's Reliance Industries has committed to a staggering $300 billion investment in building a new mega oil refinery in Texas the first greenfield refinery in the United States in nearly 50 years. President-elect Donald Trump has personally described the project as a 'historic deal' and a great win for America.

The proposed refinery, to be located near Corpus Christi, will have a capacity of 1 million barrels per day and is expected to create over 50,000 direct and indirect jobs. It will process American shale oil and produce high-grade fuels and petrochemicals, significantly boosting domestic energy production and exports.

Analysts see this investment as more than just a commercial decision. It represents a clear strategic alignment with Trump's "Make America Great Again" (MAGA) agenda, which emphasises energy independence, job creation, and reducing reliance on foreign oil. By choosing Texas, Trump's political stronghold and committing one of the largest single foreign investments in US history, Reliance has positioned itself as a key partner in America's energy resurgence.

For India, the project serves multiple purposes. It secures long-term access to American crude, diversifies oil import sources away from West Asia, and strengthens bilateral economic ties at a time when both nations are looking to

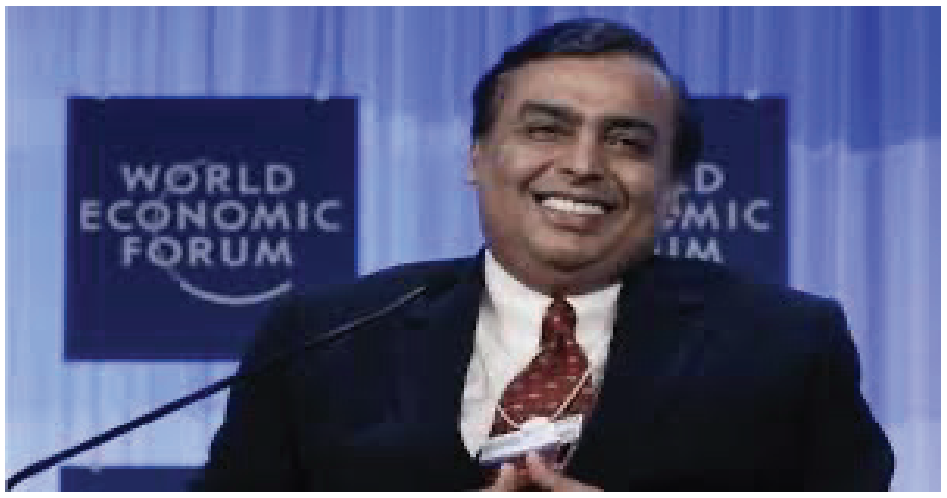

counter China's influence. It also gives Reliance a strong foothold in the world's largest energy market.

Mukesh Ambani reportedly told Trump during a recent call that the project reflects "shared values of energy security, economic growth, and strategic partnership. The US President-elect responded by calling Ambani a great friend of America.

While environmental groups have raised concerns over the project's carbon footprint, the Trump administration is expected to fast-track approvals. The deal is being viewed as a major diplomatic and economic victory for both India and the incoming US administration.

Jio Payments Bank Launches UPI-Based Cash Withdrawal Service Across India

Customers can now withdraw cash from 6 lakh+ retail outlets using UPI without debit card; Major push to deepen financial inclusion in semi-urban and rural areas

Mumbai: Jio Payments Bank has introduced a convenient UPI-based cash withdrawal facility, allowing customers to withdraw cash from over six lakh retail stores, kirana shops, and business correspondents across the country without needing a debit card or ATM visit.

The new service, named 'JioCash', enables users to generate a UPI QR code or enter their UPI ID at any participating merchant outlet and withdraw cash instantly. The service is currently available for amounts ranging from ₹100 to ₹10,000 per transaction, with daily limits aligned with RBI guidelines. It works on both Android and iOS devices and is interoperable with all major UPI apps.

Speaking at the launch, Jio Payments Bank CEO said, This is a game-changing step towards making banking truly accessible. In a country where millions still rely on cash for daily transactions, JioCash brings banking to the doorstep of every Indian, especially in tier-3, tier-4 towns and villages where ATMs are scarce.

The bank has partnered with a large network of merchants, including small shopkeepers, petrol pumps, medical stores, and FMCG distributors. The service is expected to significantly reduce the dependence on physical ATMs and cash-in-transit logistics while promoting digital payment habits among users who prefer cash.

Industry experts have welcomed the move, noting that UPI-based cash withdrawal could become a preferred channel for last-mile cash access. It also strengthens Jio Payments Bank's position in the rapidly evolving digital banking space, competing with Airtel Payments Bank and other players.

Jio Payments Bank, which already has over 10 crore savings accounts, aims to onboard another 5 crore customers in the next 18 months through this and other customer-centric innovations.

वरुण बेवरेजेस दक्षिण अफ्रीका की क्रिकली डेयरी का अधिग्रहण करेगी

पेप्सिको के प्रमुख बॉटलर ने अफ्रीका में पहला बड़ा कदम उठाया, डेयरी और जूस सेगमेंट में प्रवेश; वैश्विक विस्तार रणनीति को नई गति

नई दिल्ली: वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो भारत में पेप्सिको के सबसे बड़े बॉटलर के रूप में जानी जाती है, ने दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख डेयरी कंपनी क्रिकली डेयरी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह वरुण बेवरेजेस का अफ्रीकी महाद्वीप में पहला बड़ा अधिग्रहण है और कंपनी की वैश्विक विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

सौदे के तहत वरुण बेवरेजेस क्रिकली डेयरी की 100% हिस्सेदारी हासिल करेगी। हालांकि सौदे की सटीक राशि अभी गोपनीय रखी गई है, सूत्रों के अनुसार यह 800-1,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। क्रिकली डेयरी दक्षिण अफ्रीका में दूध, दही, चीज, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रमुख उत्पादक है और देश के कई प्रांतों में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती है।

वरुण बेवरेजेस के प्रबंध निदेशक रवि जौहर ने कहा, अफ्रीका में बढ़ती उपभोक्ता मांग और हमारी मजबूत बैलेंस शीट को देखते हुए यह सही समय है। क्रिकली डेयरी के साथ हम न केवल डेयरी सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। यह अधिग्रहण वरुण बेवरेजेस की अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है। कंपनी पहले ही नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को और जाम्बिया में सक्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में डेयरी बाजार तेजी से बढ़ रहा है और यह सौदा कंपनी को नई जियोग्राफी और प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों में मजबूती देगा।

वरुण बेवरेजेस के शेयर बाजार में इस खबर के बाद की तेजी दर्ज की गई। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार से कुल राजस्व का 25% हासिल करना है।

रेडिको खैतान का मैजिक मोमेंट्स 80 लाख केस बिक्री पार, भारत के वोडका बाजार पर 60% कब्जा

देश की सबसे लोकप्रिय वोडका ब्रांड बनी मैजिक मोमेंट्स, प्रीमियम और फ्लेवर्ड वेरिएंट्स ने तेजी से बाजार हासिल किया; अल्कोहल इंडस्ट्री में नया कीर्तिमान

नई दिल्ली: रेडिको खैतान लिमिटेड की फ्लैगशिप वोडका ब्रांड 'मैजिक मोमेंट्स' ने एक और उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने आज घोषणा की कि ब्रांड की सालाना बिक्री 80 लाख केस (8 मिलियन केस) के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही मैजिक मोमेंट्स अब भारत के पूरे वोडका बाजार में 60% हिस्सेदारी के साथ स्पष्ट रूप से नंबर-1 ब्रांड बन गई है। मैजिक मोमेंट्स ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने रेगुलर वोडका के अलावा ग्रीन एप्पल, ऑरेंज, लेमन, व्हाइट क्रैनबेरी और ट्रिपल डिस्टिल्ड प्रीमियम वेरिएंट्स लॉन्च कर युवा उपभोक्ताओं को आकर्षित किया। खासकर मेट्रो और टियर-1 शहरों में पार्टी संस्कृति और प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड ने ब्रांड को मजबूत आधार दिया।

रेडिको खैतान के चेयरमैन अभिषेक खैतान ने कहा, मैजिक मोमेंट्स न सिर्फ हमारी सबसे सफल ब्रांड है, बल्कि यह भारतीय वोडका उद्योग का चेहरा बन चुकी है। 80 लाख केस की बिक्री और 60% मार्केट शेयर एक साथ हासिल करना हमारे लिए गर्व की बात है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि रेडिको खैतान ने बेहतरीन मार्केटिंग, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट इनोवेशन के जरिए इस मुकाम को हासिल किया है। कंपनी अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार कर रही है और कुछ चुनिंदा देशों में निर्यात शुरू कर चुकी है। वर्तमान में भारतीय वोडका बाजार सालाना 12-14% की दर से बढ़ रहा है। मैजिक मोमेंट्स की इस सफलता से रेडिको खैतान के शेयर में भी की तेजी देखी गई।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.
EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23115	24573	24218	23666	23311	22759	22404	21852
BANK NIFTY	53427	57197	56376	54901	54080	52605	51784	50309
SENSEX	74207	79206	78103	76155	75052	73104	72001	70053
FINNIFTY	24781	26910	26461	25621	25172	24332	23883	23043
MIDCAP	12626	13615	13327	12977	12689	12339	12051	11701
ACC	1386	1475	1443	1414	1382	1353	1321	1292
AXISBANK	1206	1331	1295	1251	1215	1171	1135	1091
ABCAPITAL	311	346	338	324	316	302	294	280
BHARTIARTL	1845	1984	1926	1886	1828	1788	1730	1690
BHEL	262	286	276	269	259	252	242	235
BIOCON	380	412	400	390	378	368	356	346
BEL	427	469	458	443	432	417	406	391
CDSL	1192	1323	1283	1238	1198	1153	1113	1068
DATAPATTERN	3209	3693	3534	3372	3213	3051	2892	2730
ESCORTS	3086	3463	3301	3193	3031	2923	2761	2653
EICHERMOTOR	6925	7539	7304	7114	6879	6689	6454	6264
FEDERAL BANK	267	293	284	275	266	257	248	239
GRINFRAPOJECT	862	1058	1015	939	896	820	777	701
HDFCBANK	781	909	879	830	800	751	721	672
HCLTECH	1335	1456	1417	1376	1337	1296	1257	1216
HINDUNILVR	2095	2283	2235	2165	2117	2047	1999	1929
HAL	3783	4139	4066	3924	3851	3709	3636	3494
HYUNDAI	1957	2080	2044	2001	1965	1922	1886	1843
IOC	145	166	160	153	147	140	134	127
ICICIBANK	1248	1340	1319	1283	1262	1226	1205	1169
INFY	1259	1371	1331	1295	1255	1219	1179	1143
ITC	300	321	315	308	302	295	289	282
KOTAKBNK	367	389	383	375	369	361	355	347
LICHOUSING	485	527	518	501	492	475	466	449
LT	3438	3829	3734	3586	3491	3343	3248	3100
LUPIN	2319	2453	2396	2357	2300	2261	2204	2165
MARUTI	12615	13837	13506	13061	12730	12285	11954	11509
M&M	3072	3580	3408	3240	3068	2900	2728	2560
MGL	960	1098	1070	1015	987	932	904	849
MAZGAONDOC	2326	2646	2555	2441	2350	2236	2145	2031
PFC	412	472	453	433	414	394	375	355
RECLTD	330	366	357	344	335	322	313	300
RELIANCE	1414	1509	1469	1442	1402	1375	1335	1308
SBIN	1058	1132	1109	1083	1060	1034	1011	985
SUNPHARMA	1771	1893	1856	1813	1776	1733	1696	1653
SHRIRAMFINANCE	938	1110	1069	1004	963	898	857	792
TITAN	4120	4369	4272	4196	4099	4023	3926	3850
TCS	2397	2603	2543	2470	2410	2337	2277	2204
TATAMOTORS	315	351	340	328	317	305	294	282
UPL	621	670	652	637	619	604	586	571
VALIENT	269	376	325	297	246	218	167	139
WIPRO	191	207	202	197	192	187	182	177

भारत जून 2028 से सोलर प्रोजेक्ट्स में लोकल इंगॉट और वेफर अनिवार्य करेगा

स्वदेशी सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट, चीन पर निर्भरता कम करने का बड़ा कदम; 500 GW रिन्यूएबल लक्ष्य को मिलेगा मजबूत समर्थन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जून 2028 से सभी सरकारी और निजी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सोलर इंगॉट और वेफर (सोलर सेल बनाने का कच्चा माल) का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। केवल भारत में बने इंगॉट और वेफर वाले मॉड्यूल ही सरकारी योजनाओं और पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत योग्य होंगे।

यह फैसला 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में भारत सोलर वेफर और इंगॉट का लगभग 90% आयात करता है, जिसमें चीन का हिस्सा सबसे अधिक है। सरकार का मानना है कि इस निर्भरता को कम किए बिना 2030 तक 500 गीगावॉट नॉन-फॉसिल ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।

नए नियम के अनुसार, 2028 के बाद किसी भी नए सोलर प्रोजेक्ट में विदेशी इंगॉट या वेफर वाले मॉड्यूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत में सोलर मॉड्यूल की क्षमता 100 GW से अधिक हो चुकी है, लेकिन इंगॉट और वेफर की क्षमता अभी बहुत कम है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा, यह कदम न सिर्फ स्वदेशी उद्योग को मजबूत करेगा बल्कि सोलर पावर की असली आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। उद्योग संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ कंपनियों ने 2028 तक पर्याप्त क्षमता बनाने के लिए और अधिक समय और सब्सिडी की मांग की है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नीति से 2028-30 के बीच घरेलू इंगॉट-वेफर उत्पादन में भारी निवेश आएगा और हजारों नौकरियां सृजित होंगी।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in